

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



7th October 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

7th October 2022

1. - आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना:	3
(i) के बारे में:	3
2. - ओपेक:	4
(i) ओपेक के बारे में:	4
3. - यूएनएचआरसी:	5
(i) के बारे में:	5
(ii) गठन:	5
(iii) सदस्य:	5
(iv) तरीके और तकनीक:	5
(v) मुद्दे:	6
4. - बांधवगढ़ गुफाएं:	7
(i) के बारे में:	7
(ii) कुछ निष्कर्ष हैं:	7



संपादकीय विश्लेषण 8

1. दिवाला और दिवालियापन संहिता:..... 8

- (i) दिवालियापन और दिवाला संहिता वास्तव में क्या है? 8
- (ii) 2016 दिवाला और दिवालियापन संहिता: 8
- (iii) कोड द्वारा एक नया कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है। इस रणनीति ने समय-सीमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की औपचारिकता और निष्कर्ष को कारगर बनाने में मदद की। निम्नलिखित घटक रूपरेखा बनाते हैं: 8
- (iv) दिवाला और दिवालियापन संहिता के लक्ष्य हैं: 9

2. भारत के नए आईटी नियम: 10

- (i) महत्वपूर्ण प्रावधान: 10
- (ii) इन नियमों में निम्नलिखित समस्याएं हैं: 10
- (iii) एक बिचौलिए को कार्रवाई के व्यवहार्य मार्ग से वंचित करता है: 10

GURU DEEKSHAA IAS



1. - आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना:

GS II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

➤ संदर्भ:

- वित्त मंत्रालय ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) उधार सीमा का विस्तार किया, जिससे एयरलाइंस को रुपये तक उधार लेने की इजाजत मिली। 1,500 करोड़, या उनके मौजूदा कर्ज का 100%।

के बारे में:

- इसका उद्देश्य अतिरिक्त वाणिज्यिक ऋण का विस्तार करना है जो कि MSMEs, कॉर्पोरेट संस्थाओं, MUDRA उधारकर्ताओं और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को 29 फरवरी, 2020 तक उनके बकाया ऋण के अधिकतम 20% तक पूरी तरह से गारंटीकृत और संपार्श्विक-मुक्त है।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है जबकि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) ऋण प्रदान करते हैं।
- उधारकर्ता इस योजना में भाग ले सकते हैं यदि उनके पास 29 फरवरी, 2020 तक कुल 50 करोड़ रुपये तक का ऋण बकाया था, और यदि उनका वार्षिक राजस्व 250 करोड़ रुपये तक था।

- 1 अगस्त को, सरकार ने उधार ली जाने वाली ऋण की अधिकतम राशि में वृद्धि की और रुपये के दायरे को विस्तृत किया। डॉक्टरों, वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट सहित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेशेवरों को दिए गए ऋण को कवर करने के लिए 3 लाख करोड़-ईसीएलजीएस कार्यक्रम।
- योजना द्वारा दी जाने वाली चार साल की ऋण अवधि में एक साल का मूल भुगतान अधिस्थगन शामिल है।
- यह योजना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए व्याज दरों को 9.25 प्रतिशत और एनबीएफसी के लिए 14 प्रतिशत पर सीमित करती है।
- वर्तमान परिस्थिति कुल रु. अब तक 1.48 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। ईसीएलजीएस वेबसाइट पर सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत 60.67 लाख उधारकर्ताओं को 2.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

• स्रोत→ हिन्दू



2. - ओपेक:

गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला 2019 तक ओपेक बनाने वाले 14 देश बनाते हैं।

GS II

विषय→अंतरराष्ट्रीय संगठन:

- स्रोत→ हिन्दू

➤ संदर्भ:

- महत्वपूर्ण ओपेक + आपूर्ति कटौती की घोषणा के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, गैसोलीन और डीजल समायोजन के लिए छह महीने की रिकॉर्ड तोड़ कीमत फ्रीज को बढ़ाया जाएगा।

ओपेक के बारे में:

- 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की स्थापना की। ओपेक एक सतत अंतराष्ट्रीय संगठन है।
- वैश्विक बाजार में तेल की कीमत को स्थिर करने के प्रयास में और अस्थिरता से बचने के लिए जो तेल उत्पादक और उपभोग करने वाले दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएगा, यह तेल की आपूर्ति को सीमित करने के लिए काम करता है।
- उनका प्रधान कार्यालय ऑस्ट्रिया के विएना में स्थित है।
- एक राष्ट्र ओपेक का सदस्य बन सकता है यदि वह अपने आदर्शों का पालन करता है और महत्वपूर्ण मात्रा में तेल का निर्यात करता है।
- गैबॉन की सदस्यता जनवरी 1995 में समाप्त कर दी गई थी। लेकिन जुलाई 2016 में, यह एक बार फिर संगठन में शामिल हो गया।
- ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया,



3. - यूएनएचआरसी:

सदस्य:

GS II

विषय→अंतरराष्ट्रीय संगठन:

➤ संदर्भ:

- सऊदी अरब के विदेश मंत्री अली साबरी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र के दौरान एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि श्रीलंका को जिनेवा स्थित निकाय से "बहुत कम" समर्थन मिलेगा।

- यह 47 देशों से बना है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा चुने गए थे।
- UNGA इस क्षेत्र में उम्मीदवार राज्यों की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं और दायित्वों के साथ-साथ मानव अधिकारों की उन्नति और रक्षा में उनके योगदान पर विचार करता है।

तरीके और तकनीक:

के बारे में:

- मानवाधिकार परिषद, एक वैश्विक संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा के रूप में कार्य करता है, को दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और रक्षा को मजबूत करने का काम सौंपा गया है।

- संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य में मानवाधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का लक्ष्य है।
- परिषद के "थिंक टैंक" के रूप में, सलाहकार समिति कुछ विषयगत मानवाधिकार चुनौतियों पर अंतर्दृष्टि और सुझाव प्रदान करती है।

गठन:

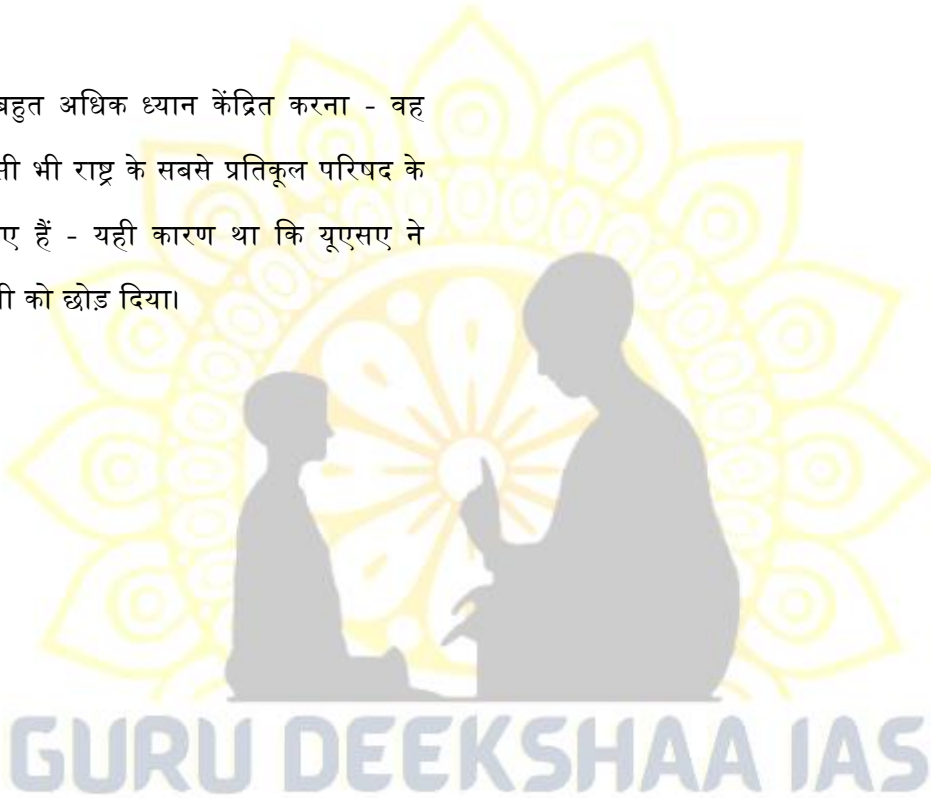
- परिषद की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। पुराने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह इस आयोग ने ले ली।
- मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय में मानवाधिकार परिषद (OHCHR) का सचिवालय है।
- OHCHR का प्रशासनिक केंद्र जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

- लोग और संगठन शिकायत प्रक्रिया के माध्यम से परिषद को मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूचना दे सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रोटोकॉल ये विशेष संबंधियों, विशेष प्रतिनिधियों, तटस्थ विशेषज्ञों और कार्य समूहों से बने होते हैं जो विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की स्थिति सहित कई विषयों पर नजर रखते हैं, देखते हैं, सलाह देते हैं और रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं।



मुद्दे:

- परिषद की सदस्यता, जिसमें कभी-कभी मानवाधिकारों के उल्लंघन के इतिहास वाले देश शामिल होते हैं, ने कुछ तिमाहियों से तीखी आलोचना की है।
- चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, रूस, वेनेजुएला और अन्य देशों पर वैश्विक मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन का आरोप है।
- इजराइल पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना - वह देश जिसने किसी भी राष्ट्र के सबसे प्रतिकूल परिषद के फैसले प्राप्त किए हैं - यही कारण था कि यूएसए ने 2018 में एजेंसी को छोड़ दिया।
- स्रोत → हिन्दू





4. - बांधवगढ़ गुफाएं:

GS I

विषय→भारतीय संस्कृति:

➤ संदर्भ:

- मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शोध किया है और अभी-अभी अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है। एएसआई के अनुसार, पड़ोसी उत्खनन में दूसरी शताब्दी से बौद्ध गुफाएं और आठवीं और नौवीं शताब्दी से हिंदू मंदिरों का पता चला। विष्णु के अवतारों को चित्रित करने वाली आठ मूर्तियों का वर्णन किया गया है।

शासकों भीमसेना, पोथासिरी और भट्टदेव का उल्लेख करते हैं।

- नौवीं और ग्यारहवीं शताब्दी के बीच, कलचुरी युग में 26 मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त दो शैव मठों का भी उल्लेख किया गया है। सबसे पुरानी एलोरा और एलीफेंटा गुफा प्रणाली भी कलचुरी राजवंश से जुड़ी हुई है, जिसने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।
- गुप्त काल के गुफा चित्र और दरवाजे के जंब भी खोजे गए हैं।

• स्रोत→ हिन्दू

के बारे में:

- भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाने वाली अखंड मूर्तियों में से एक वराह मूर्तिकला है।

कुछ निष्कर्ष हैं:

- दूसरी और पांचवीं शताब्दी के बीच 26 बौद्ध गुफाएं थीं। गुफाओं में महायान बौद्ध स्थलों की कुछ कलाकृतियाँ हैं, जिनमें पत्थर के बिस्तर और "चैत्य" (गोल) प्रवेश द्वार शामिल हैं। इस गुफा के जुड़ने से बांधवगढ़ में अब 76 ज्ञात गुफाएं हैं, जो पिछले सर्वेक्षण के दौरान 50 से अधिक हैं।
- दूसरी से पांचवीं शताब्दी तक के 24 ब्राह्मी शिलालेख हैं। शिलालेखों में मथुरा, कौशाम्बी, पावत, वेजबरदा और सपतनैरिका जैसे स्थानों का उल्लेख मिलता है। वे



संपादकीय विश्लेषण

2016 दिवाला और दिवालियापन संहिता:

1. दिवाला और दिवालियापन संहिता:

- इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) से पहले इनसॉल्वेंसी को हल करने के लिए आवश्यक लंबी प्रक्रिया का कोई आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं था। IBC का उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के संचालन को आसान बनाना है। IBC में 255 घटक और 11 अनुसूचियां हैं।

दिवालियापन और दिवाला संहिता वास्तव में क्या है?

- भारत का दिवाला कानून, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC), एक एकीकृत दिवाला और दिवालियापन कानून पेश करके मौजूदा ढांचे में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है।
- एक देनदार जो अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ है उसे दिवालिया कहा जाता है।
- जब कोई व्यक्ति या व्यवसाय दिवालिया हो जाता है और अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो वे दिवालियापन के लिए याचिका दायर करते हैं।
- यह लेनदारों, ऐसे बैंकों की मदद करने, ऋण एकत्र करने और खराब ऋणों को रोकने के लिए स्पष्ट और तेज दिवाला प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- यह एक व्यापक दिवाला कानून है जो सभी निगमों, साझेदारियों और लोगों (वित्तीय फर्मों के अलावा) पर लागू होता है।

- कानून ने सभी पूर्व प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया और दिवालियापन और दिवाला मुद्दों से निपटने के लिए एक समान ढांचा प्रदान किया।
- यह लेनदारों को व्यवसाय करने के लिए देनदार की क्षमता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। लेनदार भी कंपनी को जल्दी से परिसमाप्त करने या उसके पुनर्जन्म के लिए जोर दे सकते हैं।

कोड द्वारा एक नया कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है। इस रणनीति ने समय-सीमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की औपचारिकता और निष्कर्ष को कारगर बनाने में मदद की। निम्नलिखित घटक रूपरेखा बनाते हैं:

- वे समाधान प्रक्रिया के प्रभारी हैं और दिवाला विशेषज्ञ हैं। वे देनदार की संपत्ति की देखभाल भी करते हैं और निर्णय लेने में सहायता के लिए लेनदारों को जानकारी देते हैं।
- दिवाला के लिए पेशेवर संगठन: दिवाला व्यवसायियों को दिवाला के लिए पेशेवर संगठनों के साथ पंजीकृत किया जाएगा। दिवाला पेशेवरों को प्रमाणित करने के लिए, परीक्षण की पेशकश की जाएगी, और एजेंसियां उनके काम के लिए एक आचार संहिता स्थापित करेंगी।
- लेनदारों को किए गए सभी भुगतान, देर से भुगतान, और ऋण पर चूक पर ध्यान दिया जाएगा। सूचनात्मक संसाधन।
- निर्णायक प्राधिकरण: वे समाधान प्रक्रिया को मंजूरी देंगे, दिवाला विशेषज्ञ का चयन करेंगे और लेनदारों के अंतिम निर्णय की पुष्टि करेंगे।



- निगम और सीमित देयता कंपनियां नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में निर्णयों की अपील कर सकती हैं।
- साझेदारी और व्यक्तियों (डीआरटी) दोनों के ऋणों पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय किए जाते हैं।
- संहिता के अनुसार स्थापित पेशेवर संघ, सूचना सेवाएं और दिवाला पेशेवर दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नियंत्रण में हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता के लक्ष्य हैं:

- भारत में मौजूदा दिवाला नियमों को समेकित और अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- भारत में दिवालियापन और दिवाला प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना होगा।
- व्यवसाय के हितधारकों सहित लेनदारों के हितों की रक्षा करना।
- व्यापार का तेजी से पुनरुद्धार।
- व्यवसाय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, लेनदारों को उनकी आवश्यक सहायता प्रदान करें, और अंततः अर्थव्यवस्था में सुलभ ऋण की मात्रा में वृद्धि करें।
- एक नई और प्रभावी पुनर्वास पद्धति का निर्माण करना जिसे व्यक्ति और व्यवसाय दोनों अपना सकें।
- भारत में दिवाला और दिवालियापन बोर्ड बनाना।
- कंपनी की संपत्ति मूल्य में सुधार।



2. भारत के नए आईटी नियम:

एक कानूनी उल्लंघन:

महत्वपूर्ण प्रावधान:

- नियमों के अनुसार, बिना अनुमति के ली गई अश्लील तस्वीरें 24 घंटे के भीतर हटा दी जानी चाहिए।
- पारदर्शिता में सुधार के लिए, दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य है कि अनुपालन रिपोर्ट का खुलासा किया जाए।
- नियम सामग्री हटाने पर विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रक्रिया के विकास के लिए प्रदान करते हैं।
- यह जानकारी को लेबल करना संभव बनाता है, जिससे ग्राहकों को यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या यह प्रायोजित, स्वामित्व, विज्ञापित या अन्यथा विशेष रूप से नियंत्रित है।

इन नियमों में निम्नलिखित समस्याएं हैं:

अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित:

- भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रो. मनुभाई डी. शाह के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि "किसी के विचारों को फैलाने की स्वतंत्रता प्रत्येक लोकतांत्रिक संगठन की जीवनदायिनी है" (1992)।
- इसलिए नियमों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि उनके द्वारा लाई गई किसी भी नई कठिनाई का पता चल सके।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विनियम (MeiTY) विकसित किए।
- हालांकि, 1961 के व्यावसायिक नियमों की दूसरी अनुसूची एमईआईटीवाई को डिजिटल मीडिया के लिए कानून बनाने की क्षमता प्रदान नहीं करती है।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस प्राधिकरण का आधिकारिक मालिक है।
- "रंगीन कानून" के रूप में जाना जाने वाला कानूनी सिद्धांत, जो तर्क देता है कि विधायिका सीधे कार्य नहीं कर सकती है यदि ऐसा करना संभव नहीं है, तो इस व्यवहार से उल्लंघन होता है।
- डिजिटल मीडिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा कवर नहीं किया गया है।
- नए आईटी नियम, जिन्हें वे अपने मूल कानून के रूप में संदर्भित करते हैं, इस प्रकार आईटी अधिनियम द्वारा उन्हें दिए गए अधिकार से परे हैं।
- इस प्रकार अधिनियम का नियमों का उल्लंघन किया जाता है।

एक बिचौलिए को कार्रवाई के व्यवहार्य मार्ग से वंचित करता है:

- एक मध्यस्थ को अब न्यायालय आदेश प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर सामग्री को निकालना आवश्यक है।
- इस मामले में कि मध्यस्थ कम समय सीमा के कारण सरकार के आदेश से असहमत है, यह इसे एक उचित उपाय से इनकार करता है।



गोपनीयता भंगः

- ट्रेसबिलिटी के लिए इन नियमों की आवश्यकता निजता के अधिकार के लिए हानिकारक है।
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ने उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की क्योंकि यह बिचौलियों को उनके संदेशों की सामग्री तक पहुँचने से रोकता था।
- यदि ट्रेसबिलिटी की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया जाता है, तो यह प्रतिरक्षा खो जाएगी, जिससे इन संचारों की सुरक्षा और गोपनीयता कम हो जाएगी।
- यह इन इंटरैक्शन से प्राप्त सभी जानकारी को दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा घुसपैठ के लिए खुला बनाता है।
- इस स्थिति में, जोखिम गोपनीयता के आक्रमण और सुरक्षित स्थान तक पहुँच प्रतिबंधों से परे हो जाता है।
- हाल के डेटा उल्लंघनों, जैसे कि कई एयरलाइनों और एक प्रसिद्ध पिज्जा डिलीवरी सेवा को प्रभावित करने वाले, डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में ऐसा करने के खतरों को उजागर करते हैं।
- नियम जल्दी से वह सब कुछ हटा देते हैं जो एक सत्तारूढ़ प्राधिकरण झूठी जानकारी से छुटकारा पाने के बजाय "फर्जी समाचार" के रूप में देख सकता है।

- नतीजतन, अंतरराष्ट्रीय फर्मों और उभरते मध्यस्थ व्यवसायों को लाभ कमाने में मुश्किल होती है।
- इसलिए, अनावश्यक वित्तीय बाधाओं को जोड़कर, ये नियम न केवल "विचारों के बाजार" में बाधा डालते हैं, बल्कि बिचौलियों के लिए आर्थिक बाजार को भी समग्र रूप से बाधित करते हैं।

परिचालन खर्चः

- नियम बिचौलियों के परिचालन खर्च में वृद्धि करते हैं, जिससे उन्हें नोडल अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी जो भारतीय निवासी हैं, की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, भारत में कार्यालयों को संचालित करने के लिए बिचौलियों की आवश्यकता होती है।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

-  First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
-  Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
-  Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 @GURU_DEEKSHAAIAS



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 GURUDEEKSHAA

